

# छोटे उद्यमी डिफेंस कॉरिडोर की जमीन पर बनाएंगे बड़ी तोपें

रक्षा क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए छोटी रक्षा इकाइयों को जमीन देने के लिए किया नियमों में संशोधन  
अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में छोटे उद्यमी भी बंदूक, तोप बनाएंगे। यहां छोटे रक्षा उद्यमियों को भी जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, राज्य सरकार ने लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर में जमीन आवंटन की शर्ती में संशोधन कर दिया है।

न्यूनतम 17.5 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर निवेश की शर्त को 7.5 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर की



17.5 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर निवेश की शर्त को 7.5 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर किया गया है।

7.5 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। डिफेंस कॉरिडोर की

नोडल एजेंसी यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी) की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नोएडा व गेटर नोएडा के लिए न्यूनतम 7 करोड़ रुपये प्रति एकड़ निवेश का मानक निर्धारित किया गया है।

ये शासनादेश नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीसीडा, लीडा और सीडा प्राधिकरणों के लिए जारी किया गया था। इसमें यूपीडा और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर शामिल नहीं था। रक्षा

उद्योगों के तहत विस्फोटक व इसी तरह की तमाम इकाइयां आती हैं। इनमें तरह-तरह की टेस्टिंग व हादसे से बचाव के लिए मानक तय हैं। इस बजह से रक्षा उद्योगों को सामान्य उद्योगों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

साथ ही प्रति हेक्टेयर न्यूनतम निवेश की शर्तों के अधीन भी नहीं रखा जा सकता। इसे देखते हुए रक्षा क्षेत्र में अब तक प्राप्त औसत के आधार पर प्रति हेक्टेयर निवेश की न्यूनतम सीमा को घटा दिया गया है।

**डिफेंस कॉरिडोर :** एमएसएमई सेक्टर के लिए खुलेगा रास्ता

डिफेंस कॉरिडोर में बड़े उद्योगों की स्थापना के साथ एमएसएमई सेक्टर को लाने की तैयारी प्रदेश सरकार ने की है। प्रदेश में डिफेंस की सहायक इकाइयों की संख्या कम है। इसलिए यूपी में लगाने वाली बड़ी रक्षा इकाइया अपनी सहयोगी इकाइयों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है।

■ राज्य सरकार ने डिफेंस की छोटी इकाइयों को यूपी में ही विकासित करने का फैसला किया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए जमीन का निवेश बड़ी बाधा थी, जिसमें 60 फीसदी से ज्यादा कटौती कर राज्य सरकार ने छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। इस फैसले से डिफेंस कॉरिडोर में यूपी में ही 500 रक्षा इकाइयों के अस्तित्व में आने का अनुमान है।